International Journal of Science and Social Science Research [IJSSSR] ISSN: 2583-7877

विकसित भारत 2047 में नीति आयोग की भूमिका का अध्ययन

प्रो. गोपाल प्रसाद[1], विकास कुमार पाण्डेय[2], श्रेया द्विवेदी[3], रोहित कुमार सिंह[4]

[1]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, **उत्तर प्रदेश, इंडिया**

[2,3,4]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, **उत्तर प्रदेश, इंडिया**

[1]**Corresponding Author Email**: drgopalprasad@gmail.com

सारांश—"विकसित भारत 2047" का राष्ट्रीय विजन भारत को अगले पच्चीस वर्षों में एक समावेशी, नवाचार–प्रधान, सतत, प्रतिस्पर्धी और उच्च–आय वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने का दीर्घकालिक खाका प्रस्तुत करता है। इस महत्त्वाकांक्षी परिवर्तन–यात्रा में नीति आयोग एक केंद्रीय संस्थागत स्तंभ के रूप में उभरता है, जो न केवल नीति–निर्माण को दिशा प्रदान करता है, बल्कि राज्यों के साथ सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा शासन के बहुआयामी आयामों को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ करता है। यह शोध पत्र नीति आयोग की रणनीतिक भूमिकाकृजैसे दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का संवर्धन, SDG लोकलाइजेशन, परिणाम–आधारित निगरानी, नवाचार एवं स्टार्टअप ईकोसिस्टम का विस्तार, मानव पूंजी का सुदृढ़ीकरण तथा हरित एवं जलवायु–संवेदनशील विकासकृका समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन दर्शाता है कि नीति आयोग पारंपरिक योजना आधारित मॉडल से आगे बढ़कर एक "थिंक–एंड–डू टैंक" की भूमिका निभाता है, जो राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित नीति समाधान तैयार करता है।इसके अतिरिक्त, शोध में यह भी स्थापित किया गया है कि डिजिटल शासन, डेटा–संचालित नीति–निर्धारण, आकांक्षी जिलों का रूपांतरण, सामाजिक सुरक्षा तंत्रों की प्रभावशीलता और अवसंरचनात्मक आधुनिकीकरण को गति देने में आयोग के प्रयास 2047 के लक्ष्य को व्यवहारिक बनाने में अत्यंत सहायक हैं। नीति आयोग द्वारा विकसित बहु–हितधारक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अन्तःस्थापन और आर्थिक सुधारों के लिए संस्थागत समर्थन, विकसित भारत के लिए आवश्यक नीतिगत चपलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। अंततः यह शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में नीति आयोग एक परिवर्तनकारी भूमिका वाला ऐसा संस्थान है, जो देश की विकास–प्रतिबद्धता, नीति–सततता और भविष्यन्मुखी दृष्टिकोण को एकीकृत करता है तथा भारत को वैश्विक विकास मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

मूलशब्द : विकसित भारत 2047, नीति आयोग, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, SDG लोकलाइजेशन, डिजिटल गवर्नेंस, डेटा–आधारित नीति–निर्धारण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, मानव पूंजी विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप ईकोसिस्टम, हरित विकास।

I. परिचय

"विकसित भारत 2047" भारत सरकार का वह दूरदर्शी विजन है, जिसके तहत भारत अगले 25 वर्षों में एक उच्च–आय, नवाचार–आधारित, समावेशी एवं सतत विकास मॉडल अपनाते हुए विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, संस्थागत, तकनीकी और अवस्थानात्मक परिवर्तन को भी शामिल करता है। इस व्यापक परिवर्तनकारी एजेण्डा को गति देने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता थी, जो न केवल नीतिगत मार्गदर्शन दे, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और

शासकीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करे। इसी संदर्भ में नीति आयोग की भूमिका अत्यंत केन्द्रीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का उद्देश्य देश को केन्द्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था (centralized planning) से बाहर निकालकर सहभागी और प्रतिस्पर्धी संघवाद आधारित नीति–निर्माण प्रणाली की ओर ले जाना था। योजना आयोग जहाँ पाँच वर्षीय योजनाओं पर केन्द्रित था, वहीं नीति आयोग का दृष्टिकोण अधिक लचील, भविष्य–केन्द्रित, data-driven और नवाचार–उन्मुख है। "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य–जैसे कि 10–12% सतत GDP वृद्धि, गरीबी का उन्मूलन, रोजगार सृजन, digital leadership, energy transformation, शिक्षा–स्वास्थ्य के मानकों में सुधार और वैश्विक उत्पादन केन्द्र के रूप में भारत का स्थान–तभी प्राप्त हो सकते हैं जब नीतियाँ राज्यों के साथ समन्वय में लागू हों, उनकी सतत समीक्षा हो और सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए वैज्ञानिक data उपलब्ध हो। नीति आयोग इन सभी आयमों में एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग–राज्यों के साथ सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है, SDG (Sustainable Development Goals) लक्ष्यों की निगरानी करता है, Aspirational Districts Programme के माध्यम से पिछड़े जिलों में तेज सुधार लाता है, अटल Innovation Mission के माध्यम से startup और नवाचार को बढ़ावा देता है, तथा DMEO के माध्यम से सरकारी योजनाओं के परिणामों का वास्तविक–समय मूल्यांकन करता है। "विकसित भारत 2047" में नीति आयोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका long-term strategic vision तैयार करना है। यह न केवल मौजूदा नीति–ढाँचे में सुधार करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों–जैसे रोजगार, तकनीकी बदलाव, energy security, climate change, urbanization, शिक्षा की गुणवत्ता–का पूर्वानुमान करके समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, नीति आयोग भारत के विकास पथ को Top-down planning के बजाय Bottom-up, data-driven, decentralised planning की ओर ले जाता है, जो एक विकसित राष्ट्र की आधारशिला है।

I.I. नीति आयोग की पृष्ठभूमि

2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग (National Institution for Transforming India) का गठन किया गया। यह परिवर्तन केवल संस्थागत ढाँचे का परिवर्तन नहीं था, बल्कि नीति निर्माण दर्शन का भी परिवर्तन था। योजना आयोग केंद्रीकृत योजना–निर्माण, पाँच वर्षीय योजनाएँ, संसाधन आवंटन पर नियंत्रणकृपर आधारित था। जबकि नीति आयोगकृसहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, डेटा–आधारित शासन, राज्य–केंद्र साझेदारी, निगरानी और मूल्यांकन कृ पर आधारित है। नीति आयोग का गठन एक ऐसे समय में हुआ जब भारतकृ वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, रोजगार के नए मॉडल, और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी गहरी परिवर्तनों का सामना कर रहा था। ऐसे समय में एक लचीले, विवेकशील, भविष्य–दृष्टि वाले संस्थान की आवश्यकता थी, जो बदलते वैश्विक परिदृ श्य के अनुरूप नीति ढाँचा तैयार कर सके। यही कारण है कि नीति आयोग आज भारत की विकास–यात्रा में एक केंद्रीय स्तंभ बन चुका है।

I.II. विकसित भारत 2047 : भारत का दीर्घकालिक विजन

"विकसित भारत 2047" का उद्देश्य भारत को उसके स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरी तरह विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना है। इसमें चार प्रमुख आयाम शामिल हैंकृ 1. **आर्थिक आयाम**: GDP को उच्च–आय स्तर तक पहुँचना, विनिर्माण, स्टार्टअप, MSME वृद्धि, निर्यात आधारित वृद्धिय 2. **सामाजिक आयाम**: शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, गरीबी का उन्मूलन, लैंगिक समानताय 3. **तकनीकी आयाम**: AI, Robotics, 5G–6G, डिजिटल गवर्नेंस, नवाचार

एवं स्टार्टअप इकोसिस्टमय 4. पर्यावरणीय एवं सतत विकास आयामः नेट–जीरो लक्ष्य, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन न्यूनता, जल संरक्षण। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस संस्थान की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह नीति आयोग है।

I.II. विकसित भारत 2047 में नीति आयोग की भूमिका का महत्व

नीति आयोग—दीर्घकालिक रणनीति तैयार करता है। विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को समन्वित दिशा प्रदान करता है। SDG Index, Health Index, Education Index जैसे टूल्स द्वारा राज्यों में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। Aspirational Districts Programme द्वारा देश के पिछड़े जिलों में तेज सुधार सुनिश्चित करता है। DMEO के माध्यम से योजनाओं की वास्तविक–समय निगरानी करता है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। 2047 के लक्ष्य केवल "योजनाएँ बनाने" से नहीं प्राप्त होंगे, बल्कि निरंतर मूल्यांकन, सुधार और डेटा–आधारित निर्णयों की आवश्यकता होगी। यह क्षमता नीति आयोग के पास है और इसी कारण यह भारत के विकास पथ का एक अनिवार्य संस्थान है।

I.IV. अध्ययन का औचित्य (Rationale of the Study)

यह अध्ययन आवश्यक है क्योंकि— 2047 विजन भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। नीति आयोग की भूमिका, प्रभावशीलता और सीमाओं का मूल्यांकन भविष्य की नीति–निर्माण प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और नीति आयोग इस सहयोग का प्रमुख मंच है। भारत की आर्थिक नीति में central planning से collaborative governance की ओर परिवर्तन को समझना आवश्यक है।

I.V. अध्ययन की प्रासंगिकता (Relevance)

यह शोध— नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह नीति आयोग की वर्तमान भूमिका, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है।

I.VI. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस शोध–पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैंकृ विकसित भारत 2047 विजन को समझना और उसका विश्लेषण करना। नीति आयोग की संरचना, कार्यप्रणाली और उद्देश्यों का अध्ययन करना। 2047 के लक्ष्यों में नीति आयोग के योगदान और रणनीतिक भूमिका का मूल्यांकन करना। नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों—Aspirational Districts Programme, SDG Index, AIM आदि—की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना। 2025–2047 की आर्थिक वृद्धि के लिए डेटा–आधारित मॉडल/प्रक्षेपण प्रस्तुत करना। नीति आयोग के समक्ष चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करना। भविष्य के लिए आवश्यक सुधारों और संभावित नीतिगत सुझावों को प्रस्तुत करना।

I.VII. अध्ययन का दायरा (Scope of the Study)

यह अध्ययन निम्न क्षेत्रों को कवर करता हैकृ नीति आयोग की वर्तमान संरचना एवं कार्यप्रणाली। विकसित भारत 2047 के प्रमुख स्तंभ। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत रणनीति व रिपोर्ट। राज्यों का प्रदर्शन और नीति आयोग के इंडेक्स। GDP प्रक्षेपण व आर्थिक वृद्धि मॉडल। चुनौतियाँ, अवसर और नीतिगत सुझाव

II. साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा किसी भी शोध–पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह विषय से संबंधित पूर्व शोधों, सरकारी रिपोर्टों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विश्लेषणों तथा विशेषज्ञों की टिप्पणियों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इससे शोध की पृष्ठभूमि मजबूत होती है और शोधकर्ता को यह समझने में सहायता मिलती है कि विषय पर अब तक क्या अध्ययन किया जा चुका है और किन नए पहलुओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अध्ययन में "विकसित भारत 2047" तथा "नीति आयोग की भूमिका" से संबंधित साहित्य को निम्न प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।

II.I. नीति आयोग पर आधारित साहित्य

- **NITI Aayog Annual Reports (2015–2024)**
  नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, प्राथमिकताओं, मॉनिटरिंग सिस्टम और राज्यों के साथ सहयोग को विस्तार से समझाया गया है। इन रिपोर्टों ने यह स्पष्ट किया किकृ नीति आयोग दीर्घकालिक रणनीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है, यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है, डेटा–आधारित शासन (data–driven governance) नीति आयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। इन रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और नवाचार नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्षेत्र रहे हैं।
- **Strategy for New India @ 75 (NITI Aayog, 2018)**
  इस दस्तावेज ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2022 तक के विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे। इसमें बताया गया था किकृ भारत की वृद्धि तभी संभव है जब नीति–निर्माण वैज्ञानिक हो, राज्यों और केंद्र के बीच "सहकारी संघवाद" को नई ऊर्जा दी जाए,उद्योग, शिक्षा, कृषि और अवसंरचना क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।यह दस्तावेज 2047 के दीर्घकालिक विजन के लिए आधारशिला का कार्य करता है।
- **Good Governance Reports (DMEO)**
  DMEO की रिपोर्टों से यह सिद्ध होता है किकृ योजनाओं का परिणाम तभी बेहतर आता है जब उनकी वास्तविक–समय निगरानी हो, Aspirational Districts Programme भारत के पिछड़े जिलों में सबसे तेज सुधार लाने वाला कार्यक्रम है। इन अध्ययनों ने नीति आयोग की परिणाम–केंद्रित कार्यशैली को प्रमाणित किया।

II.II. विकसित भारत 2047 से संबंधित साहित्य

- **Vision@2047 (Government of India, 2021–2023)**
  इस विजन दस्तावेज में भारत के 100 वर्षों की स्वतंत्रता पर विकसित राष्ट्र बनने की रणनीति का उल्लेख है। साहित्य में बताया गया कि 2047 तक भारत को 10–12% GDP वृद्धि,रोजगार आधारित आर्थिक मॉडल ऊर्जा संक्रमण व नेट–जीरो लक्ष्य ,मानव पूंजी आधारित वृद्धि को अपनाना होगा। यह साहित्य बताता है कि नीति आयोग इस विजन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार करता है।
- **Economic Survey of India (वित्त मंत्रालय, 2021–2024)**
  आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है किकृभारत के लिए दीर्घकालिक विकास दर 7–8% बनाए रखना आवश्यक है,नीति आयोग राज्यों में सुधार और निवेश आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रिपोर्टों में नीति आयोग के इंडेक्स (SDG Index, Health Index, Export Readiness Index) का उल्लेख किया गया है।

II.III. सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद पर साहित्य

- **Rangarajan – Srivastava (2017)**

इनका शोध बताता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत संघीय संरचना और राज्यों को नीति–निर्माण में स्वायत्तता देना उच्च आर्थिक वृद्धि की कुंजी है। नीति आयोग उसी दिशा में कार्य करता है।

- **OECD Economic Outlook (2021–2023)**
  इस साहित्य में कहा गया है कि भारत की अनिश्चितताओं को कम करने के लिएकृ आर्थिक सुधार, निवेश हेतु अनुकूल वातावरण और राज्यों के बीच प्रदर्शन आधारित प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है। नीति आयोग इस प्रक्रिया का नेतृत्व करता है।

II.IV. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर साहित्य

- **UNDP Human Development Report (2020–2022)**
  इस रिपोर्ट में उल्लेख है किकृ ैक्ळे को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचे का मजबूत होना आवश्यक है, भारत में SDG Index राज्य–स्तरीय प्रदर्शन का वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मॉडल है। इस साहित्य से स्पष्ट है कि नीति आयोग SDG के लिए भारत का उच्च–स्तरीय निगरानी संस्थान है।

II.V. नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर साहित्य

- **World Bank India Development Update (2023)**
  रिपोर्ट बताती है किकृ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) भारत में नवाचार–आधारित आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, Tinkering Labs और Incubation Centers भारत की युवा जनसंख्या को नई दिशा दे रहे हैं। इस साहित्य से नीति आयोग की स्टार्टअप इकोसिस्टम में भूमिका का पता चलता है।

II.VI. प्रेरक अध्ययन (Empirical Studies)

- **Kohli – Singh (2020):** शोध में पाया गया कि— Aspirational Districts Programme वाले जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में तेज सुधार दर्ज हुआ है। इन जिलों में governance model replicable है।
- **Sahoo (2022):** अध्ययन बताता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में— डिजिटल गवर्नेंस, परिणाम–आधारित नीति,और राज्यों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग मुख्य भूमिका निभाती है।नीति आयोग इन तीनों क्षेत्रों का प्रमुख संस्थान है।

III. अनुसंधान पद्धति

अनुसंधान पद्धति किसी भी शोध का आधार होती है, क्योंकि यह शोध की प्रक्रिया, तकनीक, उपकरण और अध्ययन के दायरे को स्पष्ट करती है। यह अध्याय बताता है कि शोध कैसे किया गया, कौन–सी पद्धतियाँ अपनाई गईं, डेटा कैसे एकत्रित किया गया, किन स्रोतों का विश्लेषण किया गया और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या रही। इस शोध में मिश्रित विधि (Mixed Method) का उपयोग किया गया है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की पद्धतियों का समावेश है।

III.I. अनुसंधान की प्रकृति (Nature of the Study)

यह शोधकृवर्णनात्मक (Descriptive), विश्लेषणात्मक (Analytical), अध्ययनात्मक (Exploratory) प्रकृति का है। यह अध्ययन नीति आयोग की भूमिका, 2047 विजन से संबंधित नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और आर्थिक प्रक्षेपणों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

III.II. अनुसंधान की डिजाइन (Research Design)

शोध में वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन अपनाया गया है। वर्णनात्मक भाग में नीति आयोग के कार्यों, ढाँचे, रिपोर्टों और कार्यक्रमों का विवरण शामिल है। विश्लेषणात्मक भाग में डेटा, रिपोर्ट, सूचकांकों (Indices), ग्राफ, और आर्थिक प्रक्षेपणों का तुलनात्मक विश्लेषण शामिल है।

III.III. डेटा के प्रकार (Types of Data)

1) **प्राथमिक डेटा (Primary Data)**– इस शोध में प्रमुख रूप से द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है, परंतु जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ विशेषज्ञ मत, नीति दस्तावेज और सरकारी अधिकारीधविशेषज्ञों के सार्वजनिक वक्तव्य प्राथमिक स्रोत माने गए हैं। (यह शोध प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आधारित नहीं है।)
2) **द्वितीयक डेटा (Secondary Data)**– शोध का मुख्य आधार द्वितीयक स्रोत हैं, जैसेकृ नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार के टपेपवद/2047 दस्तावेज, Economic Survey, RBI के आँकड़े, नीति आयोग के SDG Index, Health Index, EoDB Index DMEO रिपोर्ट, UNDP, World Bank, IMF, OECD इत्यादि की रिपोर्ट, प्रामाणिक जर्नल, शोध–पत्र, और सरकारी वेबसाइट।

III.IV. डेटा संग्रह के स्रोत (Sources of Data Collection)

1. **सरकारी स्रोतः** नीति आयोग (NITI Aayog), वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI), त्ठप्,नीति आयोग की थीमैटिक रिपोर्ट।

2. **अंतरराष्ट्रीय स्रोतः** IMF World Economic Outlook, World Bank India Update, UNDP Human Development Report, OECD Economic Surveys.

3. अकादमिक स्रोतः शोध–पत्र, जर्नल्स, थिंक–टैंक रिपोर्ट (ORF, Brookings, NCAER) यह सभी स्रोत शोध की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं।

III.V. डेटा विश्लेषण की पद्धति (Methods of Data Analysis)

इस शोध में विश्लेषण के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया गया हैकृ 1.**सामग्री विश्लेषण (Content Analysis)**: नीति आयोग के दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विश्लेषणों का सम्यक अध्ययन किया गया। 2. **तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)**: नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों (जैसे Aspirational Districts, SDG Index) के परिणामों की तुलना संबंधित राज्योंधजिलों के प्रदर्शन से की गई। 3. **आर्थिक प्रक्षेपण विश्लेषण (Economic Projections)**: GDP ग्रोथ के 2025–2047 तक के संभावित मार्गों का ग्राफ और टेबल के माध्यम से विश्लेषण किया गया। **4. सांख्यिकीय प्रस्तुति (Statistical Representation)**: ग्राफ (Line Graph), तालिका (Table), रुझान विश्लेषण (Trend Analysis) का उपयोग किया गया।

III.VI. अनुसंधान का दायरा (Scope of Study)

शोध का दायरा निम्नलिखित सीमाओं के भीतर है— नीति आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली, विकसित भारत 2047 विजन के लक्ष्य, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और तकनीकी आयाम, SDG, Aspirational Districts, AIM जैसे कार्यक्रम, 2025–2047 की आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण और नीति आयोग के सामने मौजूद चुनौतियाँ।

III.VII. अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक डेटा पर आधारित है। नीति आयोग की कुछ आंतरिक रिपोर्टें सार्वजनिक उपलब्ध नहीं हैं। आर्थिक प्रक्षेपण अनुमानित (illustrative) आधार पर हैं। राज्यों की डेटा उपलब्धता में भिन्नता है। इसके बावजूद अध्ययन अपनी प्रकृति में पर्याप्त रूप से विश्वसनीय, विश्लेषण–आधारित और नीति–उन्मुख है।

IV. डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

इस अध्ययन में भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास संकेतकों तथा नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित "विकसित भारत 2047" लक्ष्यों से संबंधित उपलब्ध माध्यमिक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण का उद्देश्य यह समझना है कि नीति आयोग द्वारा सुझाए गए सुधार, विकास मॉडल तथा संस्थागत तंत्र 2047 तक भारत की वृद्धि–पथ पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकते हैं।

IV.I. GDP वृद्धि प्रक्षेपण का विश्लेषण

नीति आयोग द्वारा विकसित भारत 2047 के लिए प्रस्तुत दीर्घकालिक अनुमानिक ढाँचे में उच्च, मध्यम और निम्नकृतीन वृद्धि परिदृश्यों का उपयोग किया जाता है। अध्ययन हेतु एक चित्रात्मक डेटासेट तैयार किया गया जिसमें 2025 से 2047 तक GDP के संभावित रुझानों का मूल्यांकन किया गया

1.निम्न वृद्धि परिदृश्यः 2025 में 4 ट्रिलियन USD से बढ़कर 2047 में केवल 8.5 ट्रिलियन USD तक पहुँचने की संभावना। यह स्थिति तब संभव है जब संरचनात्मक सुधार धीमी गति से हों। इस परिदृश्य में भारत "उच्च आय वाले राष्ट्र" की श्रेणी में नहीं पहुँच पाएगा। **2.मध्यम वृद्धि परिदृश्यः** 2025 में 4 ट्रिलियन से बढ़कर 2047 तक लगभग 13 ट्रिलियन USD का अनुमान। यदि वर्तमान सुधार–पथ जारी रहता है तथा बुनियादी ढाँचे, कौशल, और डिजिटलीकरण पर निरंतर निवेश होता रहे तो यह परिदृश्य संभव है। यह भारत को उच्च मध्यम–आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम हो सकता है। **3.उच्च वृद्धि परिदृश्यः** 2025 में 4 ट्रिलियन से बढ़कर 2047 में 17 ट्रिलियन USD तक पहुँचने की क्षमता।

इस परिदृश्य में नीति आयोग की भूमिका निर्णायक हैकृशासन–सुधार (Good Governance), नीति–स्थिरता, बड़े पैमाने पर निजी निवेश, अनुसंधान एवं नवाचार में वृद्धि, प्रभावी संघीय सहयोग इस स्थिति में भारत उच्च–आय वाले राष्ट्र के लक्ष्य के सबसे निकट पहुँचेगा।तीनों प्रक्षेपणों में 2035 के बाद वृद्धि की गति तेज होती है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश के अधिकतम उपयोग, MSME आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी–ड्रिवन विकास से जुड़ी है।उच्च वृद्धि वक्र (High Scenario) और निम्न वृद्धि वक्र (Low Scenario) के बीच लगभग 8.5द्9 ट्रिलियन USD का अंतर दिखाई देता है, जो यह सिद्ध करता है कि नीतिगत गुणवत्ता और शासन–सुधार का आर्थिक प्रगति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

IV.II. सामाजिक विकास संकेतकों का विश्लेषण

नीति आयोग के SDG India Index, HDI डेटा और विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के आधार परः

1. शिक्षाः 2047 तक "लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षा मॉडल" से साक्षरता दर 90% तक पहुँचने की क्षमता। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर नीति आयोग का योगदान महत्वपूर्ण।
2. स्वास्थ्यः चिकित्सा अवसंरचना और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के विस्तार से 2030–2040 के बीच भारत के HDI स्वास्थ्य घटक में उल्लेखनीय सुधार की संभावना।
3. गरीबी उन्मूलनः नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार भारत में तीव्र गरीबी में निरंतर कमी हो रही है। 2047 तक अत्यधिक गरीबी <1% तक पहुँचने की संभावना जताई गई है।

IV.III. नीति–सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण

नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित 4 मुख्य फोकस क्षेत्रों—Good Governance, Inclusive Growth, Sustainability, Innovation Economy—का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता हैःइनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने से उच्च वृद्धि परिदृश्य की संभावना सबसे अधिक बढ़ती है। संघीय सहयोग (Cooperative Federalism) नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ा कारक है। E–Governance सुधार राज्य स्तर पर विकास अंतर को कम कर रहे हैं।

IV.IV. डेटा विश्लेषण का निष्कर्ष

यदि नीति आयोग द्वारा सुझाए सुधार और रणनीतियाँ उच्च प्राथमिकता पर लागू की जाती हैं, तो भारत 2047 तक 17 ट्रिलियन USD तक की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। नीति आयोग का मॉडल—विशेषकर परिणाम–आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन (Outcome–based monitoring)—भारत के दीर्घकालिक विकास को संरचनात्मक रूप से मजबूत करता है।समग्र रूप से, डेटा विश्लेषण दर्शाता है कि भारत के विकास पथ में नीति आयोग "Reform Accelerator" और "Growth Engine" दोनों के रूप में कार्य करता है।

REFERENCES

Government of India / NITI Aayog Sources

1. NITI Aayog. (2021). SDG India Index & Dashboard 2020–21. Government of India.
    a. https://www.niti.gov.in
2. NITI Aayog. (2023). Viksit Bharat @2047: Vision Document (Part I–III). Government of India.
3. NITI Aayog. (2018). Strategy for New India @75. Government of India.
4. NITI Aayog. (2020). National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report. Government of India.
5. Government of India. (2023). Economic Survey 2022–23. Ministry of Finance.
6. Government of India. (2024). Digital India Annual Report. Ministry of Electronics & IT.
7. RBI. (2023). Handbook of Statistics on Indian Economy. Reserve Bank of India.

International Reports

8. World Bank. (2023). World Development Indicators. https://data.worldbank.org
9. United Nations Development Programme. (2023). Human Development Report 2023/24. UNDP.
10. International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook Database. IMF.
11. United Nations. (2022). Sustainable Development Goals Report 2022. UN.

Additional Scholarly Sources

12. Bhattacharya, S., & Patel, U. (2021). Economic reforms and growth patterns in India: A long-term assessment. Journal of Development Studies, 57(4), 512–527.
13. Panagariya, A. (2020). India Unlimited: Reclaiming the Lost Glory. Oxford University Press.
14. Kohli, A. (2019). State capacity and industrial transformation in India. Economic and Political Weekly, 54(23), 45–52.